श्री सभापति : आध घंटा जिन्होंने क्वेश्चन किया है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, this is an important issue. श्री सभापति : वह ठीक है, माननीय सदस्य जिन्होंने क्वेश्चन किया है, वे सेटिस्फाईड है तो फिर आधा घंटा किस बात का ? ...(**व्यवधान**)...

श्री संतोष बागडोदिया : सर, कोई भी मेम्बर रिक्वेस्ट कर सकता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : जनेश्वर जी आप ?

श्री संतोष बागड़ोदिया : वे सब माननीय सदस्य चले गए है। ...(**व्यवधान**)... वे सदस्य तो चले गए है।

श्री सभापति : नहीं-नहीं ये बैठे है, जनेश्वर जी।

श्री संतोष बागड़ोदिया : जनेश्वर जी, आप आधा घंटा डिसकसन के लिए रिक्वेस्ट करिए। वे एलाऊ कर देंगे, आप आधा घंटा डिसकसन के लिए रिक्वेस्ट करिए।

श्री जनेश्वर मिश्र : सर, इस पर बहस होनी चाहिए।

श्री सभापति : ठीक है, आप लिखकर भेज दीजिए।

* 170 *[The questioner* (SHRI URKHAO GWRA BRAHMA) *was absent. For answer vide* page 31]

Failure of Sarva Shiksha Abhiyan

*171. SHRI SHAHID SIDDIQUI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have assessed the failure of Sarva Shiksha Abhiyan;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that 66 per cent additional posts of primary teachers are still lying vacant; if so, the details thereof, State-wise; and

(d) the reasons for not filling the vacancies and the details of the future plan in this regard?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) to (d): It would not be correct to say that Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) is a failure as the Central and State Governments are earnestly implementing the programme in the country.

There has been considerable progress in the recruitment of teachers against sanctioned posts under the programme. At present 58% teachers have been recruited against the sanctioned posts. (Details of State-wise position are attached in Statement-I. *(See* below)

Delays in teacher recruitment in several States under SSA are mainly due to litigation and judicial stay orders. The concerned State Governments are pursuing to resolve these at their level.

Statement-I

State-wise No. of posts of elementary teachers approved and filled up for Central assistance during last three financial years (2001-2004)

S.No.	States/UTs	Total number of posts of elementary teachers approved for Central assistance during 2001—04	Against figure mentioned in Col 3, number of teachers posts filled during 2001—04
1	2	3	4
1	Andhra Pradesh	20760	25181
2	Arunachal Pradesh	1206	1206
3	Assam	4637	4637
4	Bihar	85155	0
5	Chhattisgarh	16050	9664
6	Goa	0	0
7	Gujarat	1848	1662
8	Haryana	5290	980
9	Himachal Pradesh	2091	564
10	Jammuand Kashmir	5665	5665
11	Jharkhand	38715	23408
12	Karnataka	12196	2580

1	2	3	4
13	Kerala	0	0
14	Madhya Pradesh	79713	49723
15	Maharashtra	3355	1236
16	Manipur	744	Not Available
17	Meghalaya	5016	1334
18	Mizoram	32	20
19	Nagaland	0	0
20	Often	22904	35283
21	Punjab	946	0
22	Rajasthan	11990	24816
23	Sikkim	191	191
24	Tamil Nadu	6248	6059
25	Tripura	1350	1350
26	Uttar Pradesh	134282	99586
27	Uttaranchal	2920	673
28	West Bengal	71168	14685
29	A&N Islands	39	0
30	Chandigarh	240	0
31	D& N Haveli	449	0
32	Daman & Diu	0	0
33	Delhi	0	0
34	Lakshadweep	3	3
35	Pondicherry	0	0
	TOTAL:	535203	310506

श्री शाहिद सिद्दिकी : सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान नाकाम नहीं हुआ है। खुदा करे ऐसा हो, लेकिन जैसे कि हमारे सामने तस्वीर आ रही है जो पिछले साल 3057 करोड़ रुपए दिया गया था, उसमें से 436 करोड़ रुपए खर्च होने के आंकड़े थें। उसके बाद 3360 करोड़ रुपए की और मांग आई है। टीचर्स के बारे में यह है कि 4 लाख टीचर्स भर्ती होने थे, लेकिन ड़ेढ लाख टीचर्स भी नहीं हो पाए है।

क्यों टीचर्स भर्ती नहीं पाए है, जबकि टीचर्स की कमी है ? साथ ही ज्यादा से ज्यादा यहां टीचर्स मिल सकें, इसके लिए क्या किया जा रहा है ? सर्व शिक्षा अभियान को कामयाब बनाने के लिए जो होम वर्क होना चाहिए था, मुझे लगता है कि वह होम वर्क नहीं हुआ है। अब यह सरकार इसको वाकई जमीन पर इम्पलीमेंट करने के लिए क्या कर रही है ?

Jhfkliugfujfvmujyfgvmjngyvnthfc yredchytfvjugykikuyho8uihkiyhugutgm

†Transliteration in Urdu Script.

نے کہا کہ سروشکشا ابھیان ناکام نہیں ہوا۔ خدا کرے ایسا ہو، لیکن جیسا کہ ہمارے سامنے تصویر آرہی ہے جو پچھلے سال 3057 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا، اس میں سے 436 کروڑ روپے خرچ ہونے کے آنکڑے تھے۔ اس کے بعد 3660 کروڑ روپے کی اور مانگ آئی ہے۔ ٹیچرس کے بارے میں یہ ہے کہ 4 لاکھ ٹیچرس بھرتی ہونے تھے، لیکن ڈیڑھ لاکھ ٹیچرس بھی بھرتی نہیں ہو پائے ہیں۔ کیونکہ ٹیچرس بھرتی نہیں ہو پائے ہیں۔ جب کہ ٹیچرس کی کمی ہے؟ ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ یہاں ٹیچرس مل سکیں، اس کے لئے کیا جا رہا ہے؟ سرو شکشا ابھیان کو کامیاب بنانے کے لئے جو ہوم ورک ہونا چاہئے تھا، مجھے لگتا ہے کو وہ ہوم ورک نہیں ہوا ہے۔ اب یہ سرکار اس کو واقعی زمین پر امپلی مینٹ کرنے کے لئے کیا کر رہی ہے؟

श्री अर्जुन सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के दृष्टिकोण का स्वागत करता हूं। यह अभियान कोई व्यक्तिगत अभियान नहीं है, यह सारे देश का अभियान है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। सभी पार्टियों ने मिलकर इसे स्वीकार किया है और इसे चलाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। टीचर्स की भर्ती न होने की वजह से एक व्यवधान जरूर आया है और इस संदर्भ में मुझे यह सूचित करना पड़ रहा है कि भर्ती में जो कमी हुई है उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि यह विषय अदालत में चला गया है। इस पर स्टे ऑर्डर मिला हुआ है और जब तक स्टे वेकेट नहीं होता,हम इस पर आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते है। जहां तक और परेशानियां है, मैं इस संदर्भ में आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनी है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री है। वे जैसे ही कोई सुविधाजनक तारीख देंगे, इस राष्ट्रीय समिति की बैठक होगी और इसके जितने भी पहलू है, उन सभी पहलुओं पर प्राथमिकता से विचार करके, एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाकर हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। माननीय सदस्य को यह अंदेशा नहीं होना चाहिए कि यह अभियान किसी भी प्रकार से पीछे रह जाएगा।

श्री शाहिद सिद्दिकी : सभापति जी, मंत्री जी अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में चिंतित है ? इसके लिए मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन यह सर्व शिक्षा अभियान है और माइनोरिटी दूसरे लोगों से बहुत से कारणों से ज्यादा पिछड़ी हुई है। उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए क्या इस सर्व शिक्षा अभियान में कोई खास स्कीम, कोई खास प्रोग्राम या कोई खास फोसक बनाया गया है ? अगर बनाया गया है और अगर नहीं बनाया गया है तो क्यों नहीं बनाया गया है

شری شاہد صدیقی : سبھا پتی جی، منتری جی اقلیتوں کی شکشا کے بارے میں چنتت ہیں، اس کے لئے میں ان کا بہت سواگت کرتا ہوں۔ لیکن یہ سروشکشا ابھیان ہے اور مائنارٹی دوسرے لوگوں سے بہت سے کارنوں سے زیادہ پچھڑی ہوئی ہے۔ ان کی شکشا کو بہتر بنانے کے لئے کیا اس سروشکشا ابھیان میں کوئی خاص اسکیم، کوئی خاص پروگرام یا کوئی خاص فوکس بنایا گیا ہے؟ اگر بنایا گیا ہے تو کیا بنایا گیا ہے اور اگر نہیں بنایا گیا ہے تو کیوں نہیں بنایا گیا ہے؟

†Transliteration of Urdu Script.

श्री अर्जुन सिंह : सभापति जी, सर्व शिक्षा जैसाकि इसका नाम है, यह देश के सभी बच्चों के लिए है और इसमें माइनोरिटी के बच्चे भी शामिल है । वे अलग है, ऐसी बात नहीं है । जहां तक किसी विशेष अभियान का सवाल है, तो एक बार इस नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हो जाए, उसमे सभी पार्टी के लोग रहेंगे, जो भी फैसला होगा, हम उसे कार्यान्वित करेंगे ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, आपने कहां कि 58 प्रतिशत अध्यापकों की नियुक्तियां चाहते है, कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर आ गया है, उसकी वजह से यह नहीं हो पा रहा है । यह स्टे किन प्वाइन्ट्स पर है ? क्या ऐसे प्वाइन्ट्स पर है ? जिनका समाधान आप नहीं कर सकते है ? यदि आप समाधान कर सकते है तो कोर्ट का इंतजार क्यों कर रहे है?

श्री अर्जुन सिंह : सभापति महोदय, हम इंतजार नहीं कर रहे है । सवाल यह है कि कोर्ट ने अलग-अलग स्टेट में स्टे ऑर्डर दिए है । सभी स्टे ऑर्डर्स समान रूप से नही है । आपका जो संकेत है, इसे ध्यान में रखतु हुए हम प्रयास करेंगे कि स्टे ऑर्डर्स को वेकेट कराने के लिए हम अपनी ओर से क्या कर सकते है, हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : सभापति महोदय, भारत के संविधान में विशेष रूप से जो संशोधन हो गया है, जिसमें पांच साल से चौदह वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है, इसके अंतर्गत ही सर्व शिक्षा अधियान की आपकी योजना चालू हुई है । इसमें विशेष रूप से इसलिए कठिनाई आ रही है कि राशि आप दे रहे है, उसमें करोड़ो रुपए आप छोटी-छोटी पुस्तकें खरीदने के लिए दे रहे है, टी.वी. के लिए दे रहे है, जिनका गांव में कोई उपयोग नहीं है । प्रदेशों में शिक्षकों को एक हजार रुपए महीने पर रख रहे है । अगर स्टे भी हुए है तो शिक्षक, जिनको गुरुजी कहेंगे व शिक्षाकर्मी कहेंगे, उनको एक हजार रुपए माहवार दे रहे है । वे कहते है कि जो रेग्युलर पे स्केल है, हमें वह मिलना चाहिए । मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनकों पूरा स्केल देकर, बाकी की जो और बेकार की बातें इसमें शामिल की है, उनकों काटकर, पूरा वेतन देने की व्यवस्था करेंगे ?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO THE STARRED QUESTIONS

Privatisation of Madarsas and Islamic education

†*163. SHRI ABU ASIM AZMI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Madarsas and Islamic education centres are being privatized; if so, the reasons therefor;

†Original notice of the question was received in Hindi.